

बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण व साख सुविधाएँ

Hemraj Gupta

Research Scholar,

Maharaj Vinayak Global University, Jaipur

Dr. Gurupreet Kaur

Research Guide,

Maharaj Vinayak Global University, Jaipur

सार

अपने सबसे बुनियादी रूप में, एक आवास ऋण एक व्यक्ति को पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर मासिक भुगतान की एक निश्चित संख्या के भुगतान के माध्यम से एक घर की खरीद को वित्तपोषित करने की अनुमति देता है। एक व्यक्ति वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त कर सकता है, जो वित्तीय संस्थान के नियमों और शर्तों जैसे पात्रता आवश्यकताओं और आय आवश्यकताओं के अधीन है। आज की आधुनिक दुनिया में, विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थान ग्राहकों को अलग-अलग ब्याज दरों पर ऋण लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्याज दर ऋण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकिंग क्षेत्रों में ग्राहकों की खुशी और गृह ऋण प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाएं इस तुलनात्मक शोध का प्राथमिक फोकस हैं।

मुख्य शब्द बैंक द्वारा प्रदत्त, साख सुविधाएँ।

प्रस्तावना

चूंकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए इसे लोगों की बुनियादी जरूरतों और तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगीकरण के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखना है। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार, सरकार को देश में बुनियादी आवास की जरूरतों को पूरा करना है। 1975 में, राज्य मंत्रियों का सम्मेलन इस परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया और निम्नलिखित सुझावों की सिफारिश की गई:

- ❖ देश में एक संतुलित शहरी और क्षेत्रीय विकास हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय शहरीकरण नीति तैयार की जानी चाहिए।
- ❖ एक राष्ट्रीय आवास नीति अपनाई जानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय आवास आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
- ❖ संस्थागत और अन्य वित्त के माध्यम से ग्रामीण विकास के साथ-साथ ग्रामीण आवास कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक ग्रामीण आवास निगम की स्थापना की जानी चाहिए।
- ❖ राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आवास के लिए उनके वार्षिक योजना आवंटन में से धन की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए।

- ❖ केंद्र सरकार को खाली शहरी संपत्ति पर शीघ्र कानून बनाना चाहिए, ताकि शहरी गरीबों के लिए भी आवास की स्थिति में सुधार के लिए शहरी और शहरीकरण योग्य भूमि सरकार को उपलब्ध कराई जा सके।
- ❖ उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा मकानों के निर्माण की लागत को कम किया जाना चाहिए; स्थानीय सामग्रियों का उपयोग होना चाहिए और सार्वजनिक आवास एजेंसियों के ऊपरी खर्चों में कमी होनी चाहिए।
- ❖ राज्यों के पास उपलब्ध संस्थागत वित्त का उचित अनुपात, मौजूदा निवेश को बढ़ाकर गृह निर्माण के लिए आवंटित किया जाना चाहिए; और
- ❖ ग्रामीण श्रमिकों को आवास-स्थलों के आवंटन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र को वापस स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

राज्य मंत्रियों के सुझावों पर विचार करने के बाद, भारत सरकार ने भारत में आवास की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए:

- ❖ सरकार ने 1954 में निर्माण तकनीकों और गृह निर्माण के नए तरीकों में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एनबीओ) की स्थापना की; राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को भवन निर्माण के विभिन्न पहलुओं, निर्माण सामग्री के उपयोग में सुधार और आवास के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर शोध कार्य प्रायोजित करने की आवश्यकता थी।
- ❖ सरकार ने 1970 में देश में आवास और शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण वित्त प्रदान करने के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) बनाया है, जिसमें निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवास को बढ़ावा देने पर प्राथमिक जोर दिया गया है।
- ❖ सरकार ने 1960 में गुणवत्ता जागरूकता विकसित करने और निर्माण की लागत को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) की स्थापना की; और
- ❖ अंत में, भारत सरकार ने निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने के लिए 1987 में राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) की स्थापना की और मार्च 1987 में राष्ट्रीय आवास नीति (NHP) को अपनाया।
- ❖ सामाजिक आवास योजना में केंद्र सरकार की भूमिका व्यापक दिशा-निर्देश देने, आवश्यक सलाह देने और राज्य सरकारों को ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आवास योजनाओं की देखरेख करती है और अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त आवास योजनाएं भी शुरू करती है।

भारत में आवास वित्त प्रणाली

रियल एस्टेट क्षेत्र देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजक भी है। आवास के लिए सरकार का समर्थन पारंपरिक रूप से केंद्रीकृत और राज्य आवास बोर्डों और विकास प्राधिकरणों के माध्यम से निर्देशित किया गया था। 1970 में, राज्य ने आवास और शहरी बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) की स्थापना की।

1988 में, नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक (देश के केंद्रीय बैंक) की 100% सहायक कंपनी के रूप में की गई थी, ताकि बैंक, हाउसिंग फाइनेंस बैंकों (HFBs) को पुनर्वित्त तंत्र के माध्यम से हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा दिया जा सके। और अन्य संस्थान और आवास वित्त फर्मों के लिए पर्यवेक्षी और नियामक निकाय के रूप में भी कार्य करना।

हालांकि वाणिज्यिक बैंक देश में बचत के सबसे बड़े प्रेरक थे, परंपरागत रूप से बैंक आवास के लिए उधार देने में अनिच्छुक थे क्योंकि वे उद्योग की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करना पसंद करते थे। कई बैंकों ने हाउसिंग फाइनेंस सहायक कंपनियों की स्थापना की थी जो अपने मूल बैंक से बहुत कम समर्थन या ब्याज के साथ स्वतंत्र इकाइयों के रूप में काम करती थीं।

1990 के दशक के अंत में, कम ब्याज दरों, औद्योगिक मंदी, सुस्त क्रेडिट ऑफ-टेक और पर्याप्त तरलता, और वित्तीय अविनियमन की पृष्ठभूमि के खिलाफ, वाणिज्यिक बैंकों ने अपना ध्यान थोक खंड से खुदरा पोर्टफोलियो में स्थानांतरित कर दिया। कम ब्याज दर शासन, बढ़ती डिस्पोजेबल आय, स्थिर संपत्ति की कीमतें और वित्तीय प्रोत्साहनों ने हाउसिंग फाइनेंस को आकर्षक व्यवसाय बना दिया। इसके अलावा, आवास वित्त परंपरागत रूप से कम गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की विशेषता है और आवास ऋण की भारी मांग को देखते हुए, लगभग सभी प्रमुख वाणिज्यिक बैंक आवास वित्त के कारोबार में डूब गए हैं।

आवास क्षेत्र में संसाधनों के संवर्धित प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1999-2000 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को आवास मध्यस्थ एजेंसियों को स्वीकृत/स्वीकृत किए जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों के विरुद्ध सावधि ऋण देने की अनुमति दी। (अनिवासी भारतीयों को अग्रिम सहित), इन बिचौलियों द्वारा प्रति उधारकर्ता ऋण के आकार के बावजूद, इस प्रकार, क्रमशः ग्रामीण / अर्धशहरी और शहरी / महानगरीय क्षेत्रों में क्रमशः 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये की सीमा को हटा दिया गया। इसके अलावा, इसे (एनआरआई अग्रिमों को छोड़कर) अब वर्ष के लिए आवास वित्त आवंटन के तहत वाणिज्यिक बैंकों की उपलब्धि के रूप में माना जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी निर्धारित किया है कि अब से रुपये तक का प्रत्यक्ष आवास ऋण। शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा घरों के निर्माण के लिए बैंकों द्वारा 10 लाख के साथ-साथ एनएचबी/हुडको बांड की सदस्यता प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल करने के लिए पात्र होगी। इन सभी के साथ-साथ आवास के लिए वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धिशील जमा राशि का 3% निर्धारित करने की पिछले वर्ष की नीतिगत घोषणा के परिणामस्वरूप, आवास के लिए बैंक के ऋण देने में काफी तेजी आई। इसके अलावा, आवास वित्त व्यवसाय की कम जोखिम वाली प्रकृति और धन की तैनाती के लिए वैकल्पिक रास्ते की कमी ने भी हाल के दिनों में बैंकिंग क्षेत्र को इस क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित किया है।

आवास ऋण की अवधारणा

सामान्य तौर पर, आवास एक व्यक्ति के लिए जीवन भर का सपना होता है और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह जल्द से जल्द इस सपने को पूरा करे। हाउसिंग लोन हाउसिंग फाइनेंस बैंकों और बैंकों द्वारा उन लोगों को प्रदान की जाने वाली सुविधा है जो अपने स्वयं के संसाधनों से अपना घर बनाने या खरीदने के लिए तैयार नकदी की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं।

हाउसिंग लोन लेने का निर्णय लेने के बाद, सबसे पहले उपयुक्त हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का चयन करना होता है। वर्तमान आवास ऋण बाजार इतना प्रवाहकीय है कि कोई व्यक्ति संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण का निर्णय लेने के बाद किसी भी समय किसी भी आवास वित्त संस्थान में आवास ऋण के लिए आवेदन कर सकता है, भले ही उसने

संपत्ति का चयन न किया हो या निर्माण शुरू नहीं किया हो। अधिकांश हाउसिंग फाइनेंस बैंकों के पास उनके मार्गदर्शन कक्ष हैं, जो संपत्ति के चयन में आवास ऋण के संभावित ग्राहकों की मदद करते हैं और संपत्ति प्राप्त करने या उनकी आवश्यकताओं के अनुसार घर के निर्माण की सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। हाउसिंग लोन की मुख्य विशेषताओं पर निम्नानुसार चर्चा की जा सकती है:

ऋण की मात्रा

अधिकांश एचएफबी भूमि की लागत सहित संपत्ति की लागत का 75% से 90% ऋण प्रदान करते हैं। वर्तमान प्रतिस्पर्धी आवास ऋण बाजार में आवास ऋण ग्राहक बिना किसी कठिनाई के इस ऋण का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में एचएफबी में ऋण की कुल मात्रा में स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क भी शामिल होते हैं।

ऋण की मात्रा तय करने के लिए चुकौती क्षमता भी एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। व्यवहार में एचएफबी उधारकर्ता के वार्षिक वेतन के आधार पर आवास ऋण की राशि मंजूर करते हैं। बिजनेस क्लास के मामले में, वार्षिक पी एंड एल खातों और बैलेंस शीट के आधार पर, चुकौती क्षमता तय की जाती है।

चुकौती की अवधि

आम तौर पर विभिन्न एचएफबी द्वारा पेश किए गए आवास ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 5 से 25 वर्ष तक होती है। चुकौती अवधि उधारकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु से आगे नहीं बढ़ती है यदि वह कार्यरत है या अधिकतम 65 वर्ष है।

आवास ऋण पर ब्याज

होम लोन पर ब्याज दरें पुनर्भुगतान की अवधि के साथ बदलती रहती हैं। आम तौर पर ब्याज दरों का भुगतान की अवधि के साथ सकारात्मक सह-संबंध होता है, इसका मतलब है कि पुनर्भुगतान की अधिक अवधि के साथ अधिक ब्याज दर वसूल की जाती है।

आवास ऋण के उधारकर्ता के पास ब्याज की निश्चित दर या ब्याज की एक समायोज्य या फ्लोटिंग दर के लिए जाने का विकल्प होता है। पुनर्भुगतान की सभी अवधि में ब्याज की निश्चित दर समान रहती है, जबकि फ्लोटिंग ब्याज दर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की 'रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट' से जुड़ी होती है। फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में, आवास ऋण पर ब्याज दर तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर पहले संवितरण की तारीख से नियमित रूप से संशोधित की जाती है, यदि संबंधित एचएफबी की प्राइम-लेंडिंग दर में कोई बदलाव होता है।

प्रसंस्करण और प्रशासनिक शुल्क:

कई बार आवास ऋण लेने वाले को आवास ऋण के प्रसंस्करण और प्रशासनिक शुल्क के रूप में कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। यह हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी के आधार पर 1% से 3% तक है।

समान मासिक किस्त (ईएमआई)

आवास ऋण की वसूली निर्धारित अवधि में आवास वित्त बैंकों और उधारकर्ता के बीच सहमत किस्तों द्वारा की जाती है। ऋण की किस्तों की गणना इस प्रकार की जाती है और तय की जाती है कि उपाजित ब्याज सहित संपूर्ण मूल राशि निर्धारित समयावधि में वसूल हो जाती है और इस प्रकार तय की गई ऋण किस्त को समान मासिक किस्त (ईएमआई)

कहा जाता है। ईएमआई की गणना के समय, सामान्य व्यवहार में ब्याज की गणना के दो तरीके होते हैं, या तो इसे वार्षिक रूप से परिशोधित किया जाता है या मासिक आधार पर। वार्षिक परिशोधन में आवास ऋण का ग्राहक घाटे में रहता है जबकि मासिक परिशोधन में ग्राहक को हर महीने मूल राशि कम करने के कारण कुछ लाभ मिलता है।

आवास ऋण की चुकौती

हाउसिंग लोन का पुनर्भुगतान अंतिम संवितरण के महीने के अगले महीने से शुरू होता है। लंबित अंतिम संवितरण के मामले में उधारकर्ता संवितरित ऋण के हिस्से पर ब्याज का भुगतान करते हैं। पूर्व-ईएमआई ब्याज हर महीने देय होता है, पहली ऋण किस्त की तारीख से ईएमआई शुरू होने की तारीख तक।

उद्देश्य :

1. जन समुदाय को बचत एवं निवेश के प्रति जागरूक बनाना ।
2. जनसंख्या वृद्धि के कारण सार्वजनिक बैंकों में होने वाली भीड़ को कम करना तथा निजी

निष्कर्ष

शोध की परिकल्पनाओं में शोध कार्य प्रारम्भ करने के पहले यह माना गया था कि निजी बैंकों की कार्य प्रणाली पारदर्शी व स्थिर नहीं होती हैं। परन्तु यह परिकल्पना शोध के दौरान असत्य साबित हुई, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस युग में निजी बैंक प्रबन्ध मण्डल द्वारा अधिक पारदर्शी बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही निजी बैंकों का प्रमुख उद्देश्य अब लाभ कमाना नहीं रहा बल्कि समाज सेवा करते हुये अर्थात् जनता के हितों की अधिकतम संतुष्टि करते हुये लाभ कमाना है। साथ ही बैंकिंग संरचना में आज निजी बैंक सार्वजनिक बैंकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक लगातार सार्वजनिक बैंकों के समान ग्राहकों को बहुमूल्य सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। साथ ही जनता का विश्वास भी इन बैंकों के प्रति लगातार बढ़ रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. चौधरी, रश्मी और जंझुआ, यास्मीन (सितंबर 2011), "ग्राहक धारणाएं और होम लोन के प्रति संतुष्टि", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वॉल्यूम: 2, अंक: 9, पीपी 124-128।
2. चित्रा, एन. और मुथुरानी, एम. सेलिना। (अप्रैल-जून 2015), "एचडीएफसी बैंक-चेन्नई में होमलोन के प्रति ग्राहक धारणा", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च रिव्यू, वॉल्यूम: 1, अंक: 10, पीपी 152-155।
3. गर्ग, शिव कुमार और कुमार, गजेंद्र (अक्टूबर 2014), "हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया: ए कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स", जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, वॉल्यूम: IX, नंबर: 2, पीपी 44-53।

4. गेबेंगा नुबी, टिमोथी (2010), "नाइजीरिया में एक सतत आवास वित्त की ओर: पर्याप्त आवास स्टॉक और एक रोड मैप विकसित करने की चुनौतियां"। हाउसिंगफाइनेंस इंटरनेशनल, समर, पीपी22-28।
5. घोष, सौविक (अगस्त 2014), "भारत में हाउसिंग फाइनेंस और इंडियन ओवरसीज बैंक के विशिष्ट संदर्भ के साथ होम लोन की मूल्यांकन प्रक्रिया", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च (आईजेएसआर), वॉल्यूम: 3, अंक: 8, पीपी 129 -135।
6. घोष, सौविक (सितंबर 2014), "ए स्टडी ऑन हाउसिंग फाइनेंस पॉलिसीज एंड अप्रेजल प्रोसेस ऑफ होम लोन्स इन इंडिया" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड मैनेजमेंट: वॉल्यूम:2, अंक:9, पीपी1441-1448।
7. गोमती, सी. (अक्टूबर 2014), "हरुर तालुक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए आवास ऋण पर अध्ययन", विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानविकी के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, पीपी 111-117।
8. गोविंदा, च। हरि राव, अप्पाराव एन. (नवंबर-दिसंबर 2012), "भारतीय आवास वित्त प्रणाली का आकलन: महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य", आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, वॉल्यूम: 5, अंक: 5, पीपी 11-24।
9. गुप्ता, नीति और मलेरी, अतुल (अप्रैल-जून 2012), "चैलेंजेस एंड अपॉर्च्युनिटीज फॉर मॉर्टगेज इंडस्ट्री इन इंडिया - ए स्टडी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड", ज्ञान ज्योति ई-जर्नल, वॉल्यूम: 1, अंक: 3, पीपी 70 -79।
10. गुप्ता, जे. और जैन, एस. (अक्टूबर 2012), "ए स्टडी ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू लेंडिंग प्रैक्टिसेज", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स, वॉल्यूम 2(10), पीपी 1-6 .
11. गुप्ता, उत्कर्ष और सिन्हा, ऋचा (2015), "होम लोन के प्रति उपभोक्ता के खरीद व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक तुलनात्मक अध्ययन (भारतीय स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम, इलाहाबाद के विशेष संदर्भ में)", आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, खंड:17, अंक:2, पीपी13-17।
12. हसन खान, जाबिर और शमशाद और मुस्तकीम और तारिक हसन (2012), "ए कम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ हाउसिंग शॉर्टेज एंड लेवल्स ऑफ डेप्रिवेशन इन इंडिया", यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, वॉल्यूम 27।

13. जयंती, एस.एस., राम्या। एसएस, राम्या। वी. (अप्रैल 2014), "एचडीएफसी लिमिटेड के गृह ऋण के संदर्भ में 3पी ड्राइविंग ग्राहकों की धारणा पर एक अध्ययन", द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, वॉल्यूम: 2, अंक: 4, पीपी 97-99।
14. करुणा, च। और तुलसी राव, जी. (नवंबर 2013), "इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस, वॉल्यूम: 1, अंक: 11, पीपी 1-8।
15. कटरोडिया, अंकित (2015), "एचडीएफसी बैंक के बारे में ब्रांड जागरूकता और ग्राहक की धारणा - होम लोन", मिडास टच इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम: 3, नंबर: 1 और 2, पीपी 25-30।
16. कौर, इंदरबीर (मई-जून 2013), "एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के हाउसिंग लोन का तुलनात्मक अध्ययन", बिजनेस एंड मैनेजमेंट जर्नल, वॉल्यूम: 10 अंक: 3, पीपी 57-59।
17. कौर, लखविंदरजीत (जनवरी-फरवरी 2013), "एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रदर्शन के संबंध में उपभोक्ता व्यवहार", व्यापार और प्रबंधन के आईओएसआर जर्नल, वॉल्यूम: 7, अंक: 2, पीपी 01-11
18. कौर, रवनीत (2013), "आवास वित्त संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहक संतुष्टि: आवास विकास और वित्त निगम लिमिटेड का एक तुलनात्मक अध्ययन" गैलेक्सी इंटरनेशनल इंटर डिस्प्लिनरी रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम: 1 (2), पीपी 45- 54.
19. कौर, गगनदीप (मार्च 2015), "एन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड्स एंड कंपोजिशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया", रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस रिसर्च रिव्यू, वॉल्यूम: 1, अंक: 9, पीपी 11- 20.
20. कृष्णकुमारी, एम.आर और थम्पी, पी. संतोष। (2015), "रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड कस्टमर लॉयल्टी विद रेफरेंस टू हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस", 11वें इंटरनेशनल बिजनेस एंड सोशल साइंस रिसर्च कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही, पीपी 1-11।